और उनका संशोधित जल ही जा सकेगा अन्यथा उन इकाइयों को, जो प्रदूषित करती हैं, बंद करने की दिशा में हम कदम उठाएंगे।

माननीय सदस्या ने एक पर्टिकुलर विषय मेडिकल कॉलेजेज द्वारा फेंके जाने वाले कचरे के बारे में बात कही है, अब मैं उस पर्टिकुलर विषय का तुरंत जवाब देने में अक्षम हूं, लेकिन मैं उनकी चिंता से अवगत हूं और अगर वे इस विषय में कुछ और जानकारी चाहेंगी और अगर किसी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज के बारे में उनके मन में कोई सवाल है, तो मैं उन्हें बाद में जवाब दे सकती हूं। Thank you.

*182. [*The questioner* (DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU) *was absent*]

Nirmal Bharat Abhiyan in Jharkhand

*182. DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU: Will the Minister of DRINKING WATER AND SANITATION be pleased to state:

(a) whether Government has undertaken any programmes under Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) in Jharkhand;

(b) if so, the details thereof;

(c) the quantum of funds earmarked therefor and the funds released so far; and

(d) whether the Jharkhand Government has recommended any programmes to be taken up under NBA, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Yes Sir.

(b) The Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) was implemented with effect from 1.04.2012 to 1.10.2014. The programme was under implementation in Jharkhand as well. The achievement in construction of Individual household latrines, School and anganwadi toilets and Community Sanitary Complex under Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) is as under :—

Year	IHHLs	School toilets	Anganwadi toilets	Community Sanitary Complex
2012-13	48500	613	684	43
2013-14	76818	682	163	42
2014-15 (Upto 1st Oct., 2014)	30212	350	130	15

(c) The Opening Balance, Central share released, Expenditure and Unspent balance under NBA during the last 2 years and current year in Jharkhand is as under :—

(₹ in crore)

Year	Opening balance	Release	Expenditure	Unspent balance
2012-13	102.46	41.93	18.86	132.15
2013-14	132.15	0	40.22	93.93
2014-15 (As on 1.10.2014)	93.93	0	14.43	79.50

(d) No new programme has been recommended by the State Government under NBA.

MR. CHAIRMAN: Questioner is not present. Any supplementaries? Shri Prem Chand Gupta.

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः माननीय सभापति जी, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, "निर्मल भारत अभियान" 1 अप्रैल, 2012 से शुरू हुआ और 1 अक्तूबर, 2014 को इसे बंद कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या खाली नाम बदलने से इसमें कुछ एचीवमेंट होगी? सर, यह सवाल झारखंड राज्य के विषय में है और अगर आप देखेंगे तो इन दो सालों के समय में डेढ़ लाख के आसपास इंडिविजुअल हाउस लैटरीन बनाए गए हैं, तकरीबन 1200 स्कूलों में टॉयलेट का प्रावधान किया गया और 1000 यूनिट के आसपास आंगनवाड़ियों में प्रावधान किया गया। इसको और तेजी से कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या इसमें एम.पी. फंड्स को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है? मान्यवर, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और माननीय मंत्री जी खुद गांव से आते हैं, गांव की समस्या को अच्छी तरह समझते हैं कि यह कितना कठिन और कितना इनह्युमन एक्ट है। तो इसके लिए आपकी क्या राय है और क्या सरकार के द्वारा इसमें एम.पी. फंड्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है? दूसरा, नाम बदलने से क्या फायदा होगा?

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने "निर्मल भारत अभियान" का नाम बदलने को लेकर यह जानना चाहा है कि उसका नाम क्यों बदला गया, नाम बदलने से क्या नई चीज होगी और वह कैसे ज्यादा लाभकारी होगा? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह सही बात है कि "निर्मल भारत अभियान" 1 अप्रैल, 2012 में शुरू किया गया था और उस वक्त जो यह मिशन था, उसे कई संस्थाएं मिलकर चला रही थीं। जो हाउसहोल्ड लैटरीन बनाई जाती थीं, उसमें मनरेगा का भी कंपोनेंट शामिल था, निर्मल भारत अभियान का भी कंपोनेंट शामिल था और लगभग दस प्रतिशत लाभार्थी का भी योगदान शामिल था, लेकिन 2 अक्तूबर, 2014 को "निर्मल भारत अभियान" को "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" के नाम से परिवर्तित किया गया। उसमें गांवों को अलग और जो शहरी क्षेत्र हैं उनको अलग कर दिया गया। पहले

इंडिविजुअल लैटरीन के लिए 10000/- रुपए दिए जाते थे, उसको बदल कर हमने 12,000/- रुपए का प्रावधान किया। इसमें भी बहुत से राज्यों से ये बातें सामने आई हैं कि इस 12,000/- रुपए से कोई ज्यादा लंबा-चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी जो तीन तरह की एजेन्सियां मिलकर फंड जुटाती थीं, उनको हमने अलग करके सिर्फ "स्वच्छ भारत मिशन" के तहत यह फैसला किया। दूसरा, "स्वच्छ भारत मिशन" के तहत, जैसा आपने आंगनवाड़ी का कहा, इस के लिए जो चाइल्ड वेलफेयर एंड वीमेन एंपावरमेंट का डिपार्टमेंट है, वह करेगा। उसको हमने अपनी परिधि से बाहर कर दिया है। इसी तरह से जो स्कूल्स हैं, चाहे लड़कियों के स्कूल्स हैं या लड़कों के स्कूल्स हैं या को-एजुकेशन के हैं, उनमें शौचालयों को बनाने का प्रावधान शिक्षा विभाग करेगा। इस तरह से हमने इसको तीन भागों में बांट दिया है।

मान्यवर, जैसा कि आपने झारखंड के बारे में पूछा। ये जो आंकड़े हैं, इनसे प्रतीत होता है कि झारखंड में "निर्मल भारत अभियान " के तहत ज्यादा कामयाबी, ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। जब हमने झारखंड के बारे में 2013 का बेस-लाइन सर्वे करवाया, ग्रामीण झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ 28.02 प्रतिशत ही हाउस-होल्ड ऐसे थे, जहां टॉयलेट्स का प्रावधान था। सभापति महोदय, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने बेसलाइन सर्वे कराया था उसके अनुसार यह संख्या 40 से भी बड़ी थी। आपने कहा कि सांसदों का जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का धन है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? यह तो आपकी मर्जी है कि आप पांच के पांच करोड़ इन पर लगा दो। आपको कोई रोकेगा नहीं।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Please.

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir…

MR. CHAIRMAN: No, no. Guptaji, no further discussion on this. Shri Sanjiv Kumar. ...(*Interruptions*)... No. I am sorry. It is only a supplementary question. We have taken more than five minutes on it. Please sit down. ...(*Interruptions*)... No. Please. आप पूछिए। नहीं-नहीं। ...(*Interruptions*)... Please do not take the time of your colleagues. ...(*Interruptions*)... No, no. If you are not satisfied with the answer of the Minister, take it up with the Minister.

श्री नरेश अग्रवाल : सर, अगर आप इन्हें पूछने की इजाजत नहीं देंगे, तो मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ जाएगा, क्योंकि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है।

MR. CHAIRMAN: That is a separate question, Nareshji. ...(*Interruptions*)... Please.

श्री नरेश अग्रवाल : सर, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के दिशा-निर्देशों में संशोधन करा दीजिए कि इस निधि से इस पर व्यय कर सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... That is a separate matter. ...(*Interruptions*)... आप कृपया बैठ जाइए। Shri Sanjiv Kumar.

श्री संजीव कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं झारखंड के कोयला अंचल से आता हूं, जहां कोल और मिनरल की माइनिंग की जाती है। रात-दिन माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन के प्रौसेस में इतना पॉल्यूशन हो गया है कि लोग मर रहे हैं।

श्री सभापतिः सवाल पूछिए।

श्री संजीव कुमार : सर, एक सैकिंड।

श्री सभापतिः नहीं, मुझे आलाप की जरूरत नहीं है।

श्री संजीव कुमार : सर, उस क्षेत्र में जितने भी वाटर रिजर्वायर हैं, वे सब पॉल्यूट हो चुके हैं, जिसके कारण लोग मर रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से सीधे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि 'निर्मल भारत अभियान' को 'ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन' में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इस मिशन के तहत क्या आप कोयलांचल में पीने के पानी की व्यवस्था पाइप लाइन के जरिए कर रहे हैं या नहीं?

MR. CHAIRMAN: Thank you. Please be brief with the answer.

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंहः माननीय सभापति महोदय, ब्रीफ में तो यह है कि माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वह ड्रिंकिंग वाटर का सवाल पूछ रहे हैं और यह सवाल सैनीटेशन का है। इससे ब्रीफ तो और कोई हो नहीं सकता।

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Dr. Anil Kumar Sahani.

डॉ. अनिल कुमार साहनीः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाहता हूं कि 'निर्मल भारत अभियान' के अन्तर्गत आपने दिनांक 1.4.2012 से 1-10-2014 तक चले कार्यक्रमों को बन्द किया, तो क्या इतने दिनों में झारखंड और झारखंड के सभी स्कूल और आंगनवाड़ियों में शौचालयों की व्यवस्था हो चुकी है और जो आप नया अभियान चलाने जा रहे हैं, उसके अनुसार वहां कब तक शौचालयों की स्थापना होगी और स्वच्छता आएगी और वह क्षेत्र कब तक निर्मल होगा?

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंहः सर, झारखंड के स्कूलों में टॉयलेट्स यानी शौचालयों की बात पूछी गई है, तो मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2011-12 में 1228 स्कूलों को यह सुविधा दी गई, वर्ष 2012-13 में 613 स्कूलों में शौचालय बनाए गए और वर्ष 2013-14 में 682 एवं वर्ष 2014-15 में दिनांक 12 मार्च, 2015 तक 1361 स्कूलों में शौचालय बनाए गए।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question 183.

Coverage of Indira Awaas Yojana

*183. SHRI ANUBHAV MOHANTY: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of people benefited under Indira Awaas Yojana (IAY);

(b) the number of houses sanctioned to the beneficiaries thereunder in Odisha; and